THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) and (b). Yes. In case of women the upper age limit for sterilization has been fixed at 45 years. In case of men, those above 50 years are not generally accepted for the operation.

Establishment of Cashew Research Institution

2079. SHRI PAMPAN GOWDA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to establish a Cashew Research Institution in the country ; and

(b) if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) No Sir, there is no proposal at present under the consideration of the Government of India to establish a separate Cashew Research Institution in the country Some time ago a proposal to establish a Research Institute in Kerala for research on Cashew nut shell liquid was received in the Ministry of Foreign Trade, but they have not found it feasible to agree to the proposal so far.

The I. C A R. has already established a Central Plantation Crops Research Institute with its headquarters at Kasaragod in Kerala State which deals with research on cashew as well as other Plantation Crops. This Institute is likely to be further strengthened during this plan *inter alia* for undertaking intensive research on cashew cultivation and processing.

(b) Does not arise.

बिहार में भू-दान में मिली भूमि

2080. श्री एम० एस० पुरती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूदान यज्ञ समिति को बिहार में अब तक कितनी भूमि दान में मिली है और इसमें से कितनी खेती योग्य तथा कितनी खेती योग्य नहीं है ;

(ख) क्या इसमें ऐसी भूमि भी है जिसका कब्जा दान दिये जाने के बाद भी अब तक नहीं मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और कब्जा न मिलने के क्या कारण हैं और सरकार ने कब्जा लेने के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार की सहकारी समितियों द्वारा देय बकाया राशियां

2081. श्री एम० एस० पुरती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की सहकारी समिति के जिम्मे 14 करोड़ रुपये बकाया है ;

(ख) क्या 7 करोड़ रुपये का कोई हिसाब ही नहीं मिल पा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

देश में हरिजनों तथा आदिवासियों को आवास सुविधायें

2082. श्री एम० एस० पुरती : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कितने हरिजनों तथा आदिवासियों को आवास सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं तथा सरकार इस समस्या का कब तक समाधान कर सकेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० राधारमणी) : इस देश में ऐसे हरिजनों तथा आदिवासियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है, जिनके पास मकान नहीं हैं । तो भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं कि पिछड़े वर्ग क्षेत्र तथा साधारण क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं

में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को आवास सुविधाएं दी जाएं।

दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2083. श्री एम० एस० पुरती : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रत्येक राज्य सरकार को गत दो वर्षों में कितनी धनराशि दी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : सहायता की वर्तमान प्रणाली के अनुसार, केन्द्रीय सहायता किसी एक कार्यक्रम अथवा योजना के लिये नहीं दी जाती, बल्कि केन्द्र द्वारा प्रत्येक राज्य को सहायता उनकी सम्पूर्ण वार्षिक योजना के लिये एकमुश्त ऋण तथा अनुदान के रूप में दी जाती है। दुग्ध उत्पादन वृद्धि की योजना सहित विभिन्न राज्य प्लान स्कीमों के लिये धनराशि का नियतन सम्बन्धित राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 की राज्य योजनाओं में पशु-पालन तथा डेरी उद्योग और दुग्ध आपूर्ति के लिए निर्धारित परिव्यय को प्रदर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या LT-3385/72] इस विवरण में राज्यों को (क) सांडों का सन्तति परीक्षण तथा (ख) पशु-महामारी उन्मूलन विषयक दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता का भी उल्लेख कर दिया गया है।

Missing of Books from Sapru House Library, New Delhi

2084. SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER :
SHRI M. S. SIVASWAMY :

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the reported missing of more than 600 books from the Sapru House Library, New Delhi ;

(b) if so, whether any enquiry has been constituted ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN) : (a) According to the information furnished by the Indian Council of World Affairs, 626 volumes of UN Treaty Series were missing from the Library of the Council.

(b) and (c). A report has been lodged with the Police by the Council and the matter is under investigation of the Crime Branch of Delhi Police.

Supply of an exploratory fishing vessel under Norwegian Aid Programme

2085. SHRI A. K. GOPALAN :
SHRI VAYALAR RAVI :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have received an exploratory fishing vessel free of cost under the Norwegian Aid Programme ;

(b) whether the Government have offered this vessel to Kerala Government ; and

(c) if so, the terms and conditions of the offer ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) to (c). The last exploratory fishing vessel supplied by Norway under the successive Agreements relating to the Indo-Norwegian Project was received in 1966. No vessel received under these Agreements, of which the term of the final agreement came to a close in March, 1972, has been offered to the Government of Kerala. The vessels are, however, based at Cochin. Indications have however been received of continued assistance in various spheres including fisheries. It is expected that some exploratory fishing vessels will be supplied free of cost by the Norwegian Agency for International Development. Under the procedure prescribed by the Ministry of Finance, external assistance in the form of commodities and equipment having sale value is required to be adjusted against plan ceilings. An enquiry was accordingly made from maritime State Governments, including Kerala whether they would be able to accommodate the cost of the vessels, if